the Rubber Board for a term of three years, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

(iii) CARDAMOM BOARD

Shri Shafi Qureshi: Sir, on behalf of Shri Dinesh Singh, I beg to move the following:

"That in pursuance of sub-section (3)(c) of Section 4 of the Cardamom Act, 1965, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Cardamom Board for a term of three years, subject to the other provisions of the said Act."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That in pursuance of sub-section (3)(c) of Section 4 of the Cardamom Act, 1965, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Cardamom Board for a term of three years, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

14.47 hrs.

RULES COMMITTEE

SECOND REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): Sir, I beg to move the following:

"That this House agrees with the Second Report of the Rules Committee laid on the Table on the 22nd June, 1967."

Some hon. Members rose—

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That this House agrees with the Second Report of the Rules Committee laid on the Table on the 22nd June, 1967."

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, सवालों के नोटिस की अवधि के सम्बन्ध में जो परिवर्तन किया गया है, उस से हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होता है। अब तक यह स्थिति रही है कि सवाल करने के लिए हमें दस दिन की मियाद मिलती है, लेकिन अब हमें 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा और फिर हमें जवाब मिलेगा। अगर एक महीने का सेशन होगा, तो हमारे लिए एक समस्या पैदा हो जायेगी। कई विशेष घटनायें और बातें ऐसी होती हैं, जिन के लिए इतना लम्बा नोटिस नहीं दिया जा सकता है। इस परिवर्तन से हमारा अधिकार छिन जायेगा।

Mr. Deputy-Speaker: The Rules Committee has taken all these things into consideration. If you have any grievance against it, you can refer the matter to the Rules Committee for revision. That is the only solution.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : ऐसी बात नहीं है। आप इस रिपोर्ट पर सदन की मुहर लगाने जा रहे हैं। उसके बाद यह व्यवस्था अन्तिम हो जायेगी और तब कोई अपील करता रहे, उस पर निर्णय हो, न हो। अब तक स्थिति यह है कि दस दिन की सूचना देने पर सामान्य प्रश्न को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन अगर 21 दिन की अवधि निश्चित कर दी जाती है, तो जब सदन का अधिवेशन समाप्त होने लगेगा, उस समय कठिनाई उत्पन्न होगी। उस समय यह 21 दिन की अवधि तो उपलब्ध नहीं होगी और अगर हम अल्प-सूचना प्रश्न भेजते हैं, तो उस के सम्बन्ध में नियम यह है कि मिनिस्टर चाहे, तो उस को स्वीकार करे और चाहे, तो उस को स्वीकार न करे। अब तक का हमारा